मालवा-निमाड़ के पर्यटन स्थलों की बदलेगी किस्मत

सिंहस्थ से पहले होंगे करोड़ों रुपए के विकास कार्य

भोपाल । सिंहस्थ-2028 के भव्य आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि सरकार का मुख्य फोकस उज्जैन पर केंद्रित है, लेकिन आगामी सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इंदौर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और आसपास के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का अनुमान है कि उज्जैन के साथ-साथ इन तीनों शहरों में भी श्रद्धालुओं का सर्वाधिक दबाव रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चारों शहरों को आपस में जोड़ते हुए एक विशेष योजना बनाई जा रही है, जहां यात्री सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया मप्र छग चैप्टर के चेयरमैन हेमेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि सिंहस्थ के समय लाखों श्रद्धालु इंदौर, उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर के बीच रुकेंगे। मप्र के लिए यह धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बहुत बड़ा मौका होगा। सरकार और प्रशासन इस पर लगातार बैठकें कर रहा है और कई बैठकों में हमें भी आमंत्रित किया गया है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि सिंहस्थ के लिए मप्र आने वाले श्रद्धालु उज्जैन से लेकर इंदौर, ओंकारेश्वर और अन्य कई जगहों पर भी आरामदायक यात्रा कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही सभी योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मालवा निमाड़ के इस मॉडल पर खर्च होंगे करोड़ों रुपए

राज्य सरकार मालवा-निमाड़ क्षेत्र को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के एक बड़े और एकीकृत मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर को समाहित करने वाले इस ओंकार सर्किट के विकास पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंहस्थ के अवसर पर देश और विदेशों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी, सुलभ आवास और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। संबंधित विभाग ने इस पूरी योजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

पर्यटक केंद्रों पर मिलेंगी आधुनिक और डिजिटल सुविधाएं

ओंकार सर्किट योजना के अंतर्गत इन चारों प्रमुख धार्मिक नगरों में सर्वसुविधायुक्त यात्री सुविधा और सूचना केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आने वाले यात्रियों को आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से विभिन्न धार्मिक स्थलों का अनूठा अनुभव कराया जाएगा। पर्यटक सूचना केंद्रों में मुख्य रूप से फूड कोर्ट, किचन, डिजिटल वीआर रूम, सूचना डेस्क, प्रतीक्षालय और डोरमेट्री जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके साथ ही पर्यटक सुविधा केंद्रों में रिसेप्शन, फैमिली वेटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, जनसुविधा केंद्र, पार्किंग और एआर-वीआर आधारित विशेष अनुभव कक्ष तैयार होंगे। लंबी दूरी तय करके आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए प्रमुख मार्गों पर वे-साइड एमीनिटीज भी विकसित की जाएंगी।

विशेष मोबाइल एप भी तैयार किया जा रहा

श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही और रास्तों की सही जानकारी के लिए पूरे सर्किट क्षेत्र में आधुनिक साइनेज सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा एक विशेष मोबाइल एप भी तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रूट मैप, प्रमुख दर्शन स्थल, ठहरने के स्थान, भोजन और आपातकालीन सेवाओं की सटीक जानकारी मिल सकेगी। रणनीतिक योजना के अनुसार, सिंहस्थ-2028 के दौरान इंदौर को मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में, उज्जैन को केंद्रीय आयोजन स्थल के रूप में और ओंकारेश्वर व महेश्वर को

ताल-बेताला

शशिकांत गुप्ते, मोबाइल नं. 78984-88217

विचारहीनता में विमर्श असंभव?

राजनीति से जब शास्त्र अलग कर दिया है,तब से राजनीति से नीति गायब कर दी गई। दिखावे के लिए नीति बहुत लोकलुभावन बनाई जाती है लेकिन नीति लागू करने की नीयत होती ही नहीं है।राजनीति से शास्त्र गायब होने से राजनीति में विचारधारा शून्य हो गई है।

वास्तव में यह (Political science) राजनीति शास्त्र है।

लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। राजनीति वह माध्यम या प्रक्रिया है जिसके जरिए लोकतांत्रिक देशों में नीतियां बनाई जाती हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सरल शब्दों में, राजनीति लोकतंत्र का व्यावहारिक रूप है। उपर्युक्त सैद्धांतिक मुद्दों पर गंभीरता से विचार और विमर्श होना चाहिए। विमर्श मतलब किसी भी मुद्दे पर तार्किक बहस के साथ विश्लेषण करना और योग्य निष्कर्ष तक पहुंचना,कहने का तात्पर्य विमर्श मतलब बौद्धिक बहस करना।

कुछ प्रतिशत मध्यम वर्गीय और कुछ उच्च वर्गीय लोग कहते हैं राजनीति मतलब फालतू अपने को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ऐसे उदासीन लोगों को महंगाई, बेरोजगारी पर प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए? ऐसे लोग एक ओर तो राजनीति को फालतू कहते हैं लेकिन चुनाव के समय व्यक्ति पूजा को महत्व देते हुए,भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन करने में परहेज नहीं करते हैं। ऐसा करना सिर्फ़ भ्रष्ट व्यक्ति का समर्थन नहीं है,यह तो पूरी भ्रष्ट व्यवस्था का समर्थन है।

समाजवादी विचारक,चिंतक,
स्वतंत्रता सैनानी डॉ.राममनोहर

लोहियाजी ने यहां तक कहा है कि चाय पीते वक्त चाय में एक चम्मच,दो चम्मच या आधी चम्मच शक्कर मिलाने पर विचार करना भी राजनीति ही है। इन दिनों कुछ लोग राजनीति के द्वारा फैलाए जा रहे सांप्रदायिक वैमनस्यता के शिकार होकर मतदान कर रहें हैं। विधर्मियों के विरुद्ध विष वमन कर रहें हैं। कुछ कथित साहित्यकार जो मंचों पर हास्य कविता के नाम पर फूहड़ता प्रस्तुत करते हैं और राजनीति को कोसते रहतें हैं। राजनीति को कोसना मतलब अच्छे लोगों के बीच राजनीति का भय निर्मित करना और अच्छे,नेक लोगों को सक्रिय राजनीति से दूर करने की साजिश का समर्थन करना ही तो है। कुछ सुविधाभागी लोग आपस में चर्चा करते हुए कहते हैं कि अपना देश लोकतंत्र के लायक नहीं है? जो लोग लोकतंत्र को मानने से इंकार करते हैं,उन्हें अपने जेहन में झांक कर यह तय कर लेना चाहिए कि वे मानव हैं ये पशु हैं? यदि पशु हैं तो पशुओं को हांकने वालें की निश्चित ही जरूरत होती है?

कुछ व्यंग्यकार कहलाने वालें मैचों पर अपनी वाकपटुता से प्रभावी प्रस्तुति देने में सक्षम होते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं लेकिन ऐसा व्यंग्य सिर्फ हास्य पैदा कर श्रोताओं के मनोरंजन का साधन बनता लेकिन व्यंग्य की धार भोथरी हो जाती है और जिस किसी मुद्दे पर या विषय पर व्यंग्य किया जाता है,उसमें कतई परिवर्तन नहीं होता है?

वास्तव में व्यंग्य समाज में व्याप्त कुरीतियों,रूढ़ियों, दकियानूसी सोच बदलने की एक सशक्त विधा है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है,दुर्भाग्य से कथित साहित्यकार मंचों पर हास्य व्यंग्य के नाम पर प्रस्तुति देने के लाखों रुपए मानधन वसूलते हैं। ठीक फिल्मी अभिनेता की तरह जो भिखारी,गरीब,ठग,बेईमान,चार सौ बीस,बेरोजगार और लाचार आदि होने का अभिनय तो करता है,लेकिन अभिनय करने मानधन लाखों रुपयों में प्राप्त करता है। धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ कथा वाचक लाखों रुपयों का मानधन प्राप्त करते हैं,दिव्य भव्य धार्मिक आयोजनों में भगवान राम की कथा सुनाते है। यह भूल जातें हैं कि स्वयं भगवान राम महल को त्याग कर चौदह वर्ष वन में रहे थे। वह भी पांच वृक्षों की कुटिया में। कलयुग में रामजी विशाल दिव्य भव्य मंदिर निर्मित होता है?

ऐसे अनेक व्यवहारिक प्रश्न है?

उक्त प्रश्नों पर विमर्श होना चाहिए।

पुतिन का नया हथियार, दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर

मॉस्को । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक ऐसा घातक हथियार इन दिनों दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे आसमान में ट्रैक करना नामुमकिन माना जा रहा है। यह आधुनिक हथियार पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सीधे रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि किसी जहरीले सांप की तरह हवा में जिग-जैग यानी लहराते हुए आगे बढ़ता है। इसकी अकल्पनीय रफ्तार और पल-पल अपना रास्ता बदलने की अद्भुत चालाकी के सामने पश्चिमी देशों के सबसे आधुनिक रडार सिस्टम भी पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का अरबों डॉलर की लागत से बना थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने एक लाचार खिलौने जैसा नजर आता है। वैश्विक सैन्य संतुलन को पूरी तरह से बदलने वाले इन आधुनिक हथियारों में रूस के एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का नाम सबसे ऊपर आता है। जब साल 2018 में रूस ने अपने छह सबसे घातक रणनीतिक हथियारों की घोषणा की थी।

मध्यप्रदेश में यूसीसी ने पकड़ी रफ्तार

15 जून तक सरकार को भेजा जा सकता है सुझाव

भोपाल । मध्यप्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिया की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर ऐलान बड़ा ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि एक घर दो कानून से नहीं चल पाएगा। वहीं, अब मध्यप्रदेश में मोहन सरकार यूसीसी लागू करने में तेजी ला रही है। यूसीसीएमपी की वेबसाईट लांच करने के बाद अब 15 जून तक प्रदेश के आम नागरिकों से इस संबंध में सुझाव मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये अपील साझा की है। मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारियों में जुटी है सरकार। इस बीच वेबसाइट पर मध्यप्रदेश के आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इस वेबसाइट पर प्रदेश भर से लोग समान नागरिक संहिता को लेकर 15 जून तक अपने सुझाव या वे इस संबंध में क्या सोचते हैं, अपनी राय सरकार को भेज सकेंगे। सरकार की इसके पीछे मंशा ये है कि इस प्रोसेस के जरिए सबके सुझावों और सहमति के आधार पर कानून तैयार हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जनता ज्यादा से ज्यादा तादात में अपने सुझाव दे। उसी के आधार पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।

हाईलेवल कमेटी स्टडी के बाद सौंपेगी रिपोर्ट

मध्यप्रदेश में यूसीसी को लेकर एक हाईलेवल कमेटी गठित कर दी गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर ये कमेटी 60 दिन के भीतर अलग-अलग कानून का अध्ययन करेगी और रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करेगी। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई कर रही हैं। पांच सदस्यीय समिति इनकी अध्यक्षता में है।

यूसीसी के दायरे में आएंगे ये मामले

यूसीसी के दायरे में शादी-ब्याह, तलाक से लेकर संपत्तियों के मामले जिसमें खासतौर पर परिवार में जायदाद का बंटवारा भी शामिल होंगे। इसके लिए सभी समुदाय और धर्म में अब एक ही नियाम लागू होगा। हालांकि, फाइनल ड्राफ्ट आम लोगों से मिले सुझावों और समिति की स्टडी के बाद तैयार किया जाएगा। मोहन सरकार की तैयारी है कि दीपावली के पहले मध्यप्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाए।

पटरी पर दौड़ने को तैयार देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

हैदराबाद (एजेंसी)। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। रेलवे बोर्ड ने उत्तरी रेलवे के जींद-सोनीपत खंड पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली 10 डिब्बों की इस विशेष ट्रेन को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, 1200 किलोवॉट हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रणोदन प्रणाली से लैस यह ट्रेन अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस अनूठी पहल के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो स्वच्छ रेल परिवहन के लिए हाइड्रोजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। चूंकि यह तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए दुनिया के गिने-चुने देशों में ही इसका परीक्षण या संचालन किया जा रहा है। देश में इस पर्यावरण-अनुकूल ट्रेन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सरकार इसे तेल आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा के नए विकल्प के रूप में देख रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सरकार ने शुरुआती चरण में ऐसी 35 ट्रेनों के विकास के लिए लगभग 2,800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इन ट्रेनों को मुख्य रूप से उन ऐतिहासिक और पहाड़ी मार्गों पर चलाया जाएगा।

अब तुर्की की छाती पर भारत का ब्रह्मोस तानेगा साइप्रस

निकोसिया । वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की मांग लगातार बढ़ रही है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों के बाद अब यूरोपीय देश साइप्रस ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी कामिकेज (सुसाइड) ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई है। इस संभावित रक्षा सौदे ने भूमध्य सागर में तुर्की की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह रणनीतिक योजना साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स की हालिया भारत यात्रा के दौरान बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने एक रक्षा सहयोग रोडमैप को मंजूरी दी है।

इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं ट्रेनिंग, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करेंगी। इसके साथ ही साइप्रस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल, और स्वदेशी सुसाइड ड्रोन नागास्त्र-1 व स्काईस्ट्राइकर खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यदि इस रक्षा सौदे पर अंतिम मुहर लगती है, तो यह पहला मौका होगा जब भूमध्य सागर क्षेत्र में किसी भारतीय हथियार प्रणाली की तैनाती होगी। जानकारों के मुताबिक, यह तुर्की के लिए एक बड़ा भू-राजनीतिक झटका है, क्योंकि वह पिछले कई दशकों से उत्तरी साइप्रस पर अवैध कब्जा जमाए हुए है। भूमध्य सागर में ब्रह्मोस जैसी अचूक और मारक मिसाइल की तैनाती से क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पूरी तरह बदल सकता है।

एजुकेशन पोर्टल में गड़बड़ी,मृत शिक्षकों को कार्यरत बताया

कमिश्नर ने दिए वेरिफिकेशन के निर्देश, 29 मई तक डीईओ से मांगी रिपोर्ट ; 30 को होगी बैठक

भोपाल । मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की जानकारी को लेकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 में बड़ी गड़बडियां सामने आई हैं।

कई ऐसे शिक्षक जो वर्तमान में स्कूलों में कार्यरत हैं, उन्हें पोर्टल में मृत या रिटायर्ड दर्शा दिया गया है। वहीं जिन शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें अब भी कार्यरत बताया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी का सत्यापन कर त्रुटियां सुधारने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रत्येक स्कूल में स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षक और रिक्त पदों की जानकारी अपलोड कराई गई थी। साथ ही शिक्षकों की पदस्थापना, पदनाम और विषय संबंधी जानकारी भी दर्ज की गई थी, लेकिन सत्यापन के दौरान पोर्टल पर व्यापक स्तर पर गड़बडियां सामने आईं।

संस्था, पदनाम और विषय का दोबारा सत्यापन करें

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना वाली संस्था, पदनाम और विषय संबंधी जानकारी का दोबारा सत्यापन किया जाए। इससे स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। 25 मई को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिक्त पदों के सत्यापन को लेकर चर्चा की गई थी, जिसके बाद सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों से कहा गया है कि जिला और विकासखंड स्तर पर स्कूलों में रिक्त पदों की स्थिति का वेरिफिकेशन कर आवश्यक संशोधन किए जाएं।

डीईओ रद्द करेंगे प्रविष्टि

संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों को गलती से मृत या रिटायर्ड दर्ज कर दिया गया है, उनके मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापन के बाद रद्द प्रविष्टि की कार्रवाई करेंगे। वहीं जिन स्कूलों में नेटवर्क की समस्या के कारण जानकारी अपडेट नहीं हो सकी है, वहां समन्वय बनाकर डेटा अपडेट कराया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों से कहा है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की जानकारी में संशोधन किया जाना है, उनकी अलग सूची तैयार कर 29 मई तक लोक शिक्षण संचालनालय को भेजी जाए। इसके बाद 30 मई 2026 को कमिश्नर के साथ बैठक आयोजित होगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और आईटी समन्वयक शामिल रहेंगे।

कार्टून कोना....

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: स्वच्छता में मप्र ने मारी बाजी

सिटीजन फीडबैक में पूरे देश में नंबर-1 बना मध्यप्रदेश

भोपाल । मध्य प्रदेश ने स्वच्छता के मैदान में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत शहरों की सफाई को लेकर लिए जा रहे सिटीजन फीडबैक में मध्यप्रदेश देशभर में नंबर-1 पर पहुंच गया है।

2011 की जनसंख्या के आधार पर जारी आंकड़ों में प्रदेश ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। अब तक प्रदेश के 35.69 लाख से ज्यादा नागरिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने शहर की सफाई को लेकर फीडबैक दर्ज कर चुके हैं। 27 मई तक के आंकड़ों में मध्यप्रदेश डिजिटल भागीदारी के मामले में भी देश में सबसे आगे दिखाई दिया।

1 करोड़ एसएमएस, 60 लाख लोगों तक सोशल मीडिया पहुंच

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत इस बार राज्य स्तर पर 360 डिग्री रणनीति अपनाई गई। नगरीय निकायों के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए 60 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई गई। इसके अलावा कचरा गाडियों से प्रचार, अखबार, रेडियो, टीवी और घर-घर अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता और ऑनलाइन फीडबैक के लिए जागरूक किया गया। नागरिकों को प्रेरित करने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा एसएमएस भेजे गए और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद भी ली गई।

जबलपुर-इंदौर समेत कई शहरों ने दिखाया दम

नगर निगमों में जबलपुर 52.20 प्रतिशत सिटीजन फीडबैक के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद इंदौर 40.07 प्रतिशत और उज्जैन 28.30 प्रतिशत पर रहे। नगर पालिका परिषदों में सेंधवा 69.56 प्रतिशत, विजय राघोगढ़ 63.62 प्रतिशत और आगर 37.94 प्रतिशत फीडबैक के साथ टॉप पर रहे।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सौरभ कुमार सनोडिया पिता मुन्ना प्रसाद था जिसे बदलकर मैंने अपना नाम सौरभ सनोडिया पिता मुन्ना प्रसाद रख लिया है अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम **सौरभ सनोडिया** पिता मुन्ना प्रसाद से जाना व पहचाना जाये।

सौरभ सनोडिया
पिता मुन्ना प्रसाद
एफ.सी.आई. मार्ग, गली नं 3
कस्तूरबा वार्ड, सिवनी म.प्र. 480661
मोबाइल नं. 90982 73159

स्वामी मेसर्स एसोसिएटेड प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (एम.पी.) प्रा.लि. इंदौर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मोनिका सेठ द्वारा 17, न्यू देवास रोड (संजय गांधी मार्ग) इंदौर से मुद्रित एवं 5, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित संपादक-मोनिका सेठ,
फोन नं. 3551753, 2434701, 2544433, समाचार पत्र से प्रकाशित समाचार के लिए सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा। समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार*